मेहनतकशों का पैग़ाम
Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 R.N.I. No. 66400/97

मौत का सौदागर बनी दवा परीक्षण कम्पनियां 3
अंधविश्वास के सौदागरों ने बलि चढ़ाया दाभोलकर को
भेड़ियों, दरिंदों को ही कोसना पर्याप्त नहीं 4
आसाराम के साथ है भाजपा
जनता के ख़िलाफ़ अमरीकी साजिश में 6
भारतीय पूंजीपति भी साझीदार
बिजली वाले लूटेंगे, पीटेंगे, फ़िर पुलिस ... 8
सायरन : पुलिस की शान, जनता परेशान

वर्ष 26 अंक 20 फरीदाबाद, रविवार, 1-15 सितंबर 2013 फोन : - 9999595632 सहयोग राशि 2 रुपया

हत्यारें करना हुआ आकर्षक : अदालत व पुलिस मूक दर्शक

फ़रीदाबाद (म.मो.) एक दिन-दहाड़े हत्या 19 अगस्त को करीब साढ़े ग्यारह बजे सेक्टर 15 ए स्थित टेलिफ़ोन एक्सचेंज के सामने चलती सड़क पर हुई। स्कार्पियों में बैठे फ़रीदपुर निवासी नरेन्द्र (30) को 2 पिस्टलधारियों ने 3 गोलियां मारी। करीब पौने तीन वर्ष पूर्व नरेन्द्र के भाई रवीन्द्र फ़ौजी की भी गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी।

नरेन्द्र अपने भाई की हत्या के मामले का मुदई एवं प्रमुख गवाह था। उस पर पिछले काफ़ी अर्से से 'समझौता' करने का दबाव हत्यारों की ओर से डाला जा रहा था। करीब डेढ़ वर्ष पूर्व उसने इस संवाददाता को खुद बताया था कि 'समझौता' तो वह करने वाला नहीं लेकिन हत्यारे उसे छोड़नेवाले भी नहीं। यही बात उसने सुनवाई कर रही कोर्ट तथा पुलिस को भी बताई थी। पुलिस ने उसे एक सशस्त्र सिपाही बतौर गार्ड दे रखा था।

हत्यारों ने सबसे पहले सशस्त्र गार्ड को ही काबू किया और फ़िर ताबड़तोड़ 3 गोलियां नरेन्द्र की छाती में उतार दी। घटना के वक्त नरेन्द्र व गार्ड दोनों स्कोर्पियो गाड़ी में बैठे थे। हत्यारों ने उन्हें गाड़ी से उतरने का मौका ही नहीं दिया। यद्यपि नरेन्द्र के पास भी उस वक्त लाइसेंसी पिस्तौल था, लेकिन हत्यारों ने इतनी फ़ुर्ती से काम किया कि गार्ड की एसएलआर (बंदूक) व नरेन्द्र का पिस्तौल सब धरे रह गये। गौरतलब बात यह भी है कि घटनास्थल पुलिस चौकी से 150 मीटर की दूरी पर ही है। दूसरी हत्या की दिनदहाड़े वारदात 22 अगस्त, को साढे बारह बजे बेहद चहल-पहल भरे कोर्ट परिसर में हुई। यहां से थाना सेंट्रल महज 150 मीटर दूर है तथा पुलिस जोनल मुख्यालय मात्र चंद मीटर पर है। विदित है कि कोर्ट परिसर में हर वक्त दर्जनों सशस्त्र व अनेकों अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं। इन सब से बेखौफ़ 3 सशस्त्र हत्यारे कोर्ट परिसर में आये और अपने वकील की सीट पर बैठे शशि नागर पर ताबड़तोड़ 10 गोलियां चलाकर हथियार लहराते हुए परिसर से निकल कर बाहर खड़ी अपनी स्विफ्ट कार में सवार हो कर फ़रार हो गये। रविन्द्र फ़ौजी व नागर दोनों भी कोई शरीफ़ या समाजसेवी नहीं थे। दोनों ही पेशेवर अपराधी थे। नागर पर तो इस वक्त तक 13 आपराधिक मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। आखिरी मुकदमा थाना एस जी एम नगर में तब दर्ज हुआ था जब उसने पिछले दिनों एसीपी रमेशपाल पर ही अपने साथियों सहित हमला कर दिया था।

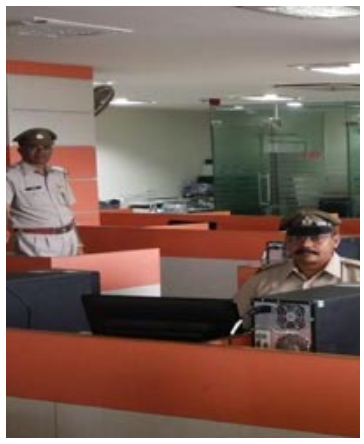

अदालत परिसर एवं पुलिस मुख्यालय : देर और अंधेर के प्रतीक

बीते 66 बरसों में इस देश के राजनेताओं एवं नौकरशाहों ने कानून एवं व्यवस्था को इस कदर अपाहिज बना दिया है कि अब अपराधियों एवं दबंगों को कानून को अपनी ठोकर पर रख कर चलने की आदत पड़ गई है।

-शेष पेज 2 पर

राजकीय नेहरू कॉलेज:

सीटों के बिना ही सीटें बढ़ा दीं सरकार ने

फ़रीदाबाद (म.मो.) शिक्षा का व्यापार करने वाली दुकानों में भले ही सीटें खाली पड़ी हों, जिन्हें बेचने के लिये शिक्षा-व्यापारी पूरे ज़ोर-शोर से विज्ञापनबाज़ी करने में जुटे हों; लेकिन ग़रीब तबकों का एकमात्र सहारा होते हैं सरकारी कॉलेज। ऐसा ही कॉलेज है यहां का नेहरू राजकीय महाविद्यालय। इसकी कुल क्षमता 1500 छात्रों की जगह यहां 4500 छात्र भरे हैं। क्षमता से तीन गुणा छात्र-छात्राओं को दाखिला दे चुकने के बाद जब सीटें समाप्त घोषित कर दी गयीं तो कुछ स्थानीय छात्र नेता राज्य के राजनेताओं से मिले और गुहार लगाई कि कॉलेज में सीटें बढाई जायें।

1971 में यह कॉलेज मात्र 400 छात्रों के लिये बनाया गया था। धीरे-धीरे समय के साथ जब छात्रों की संख्या बढने लगी तो इसकी क्षमता को 1500 तक बढा दिया गया। जाहिर है क्षमता बढाने के लिये नये कमरे बनाये गये, विज्ञान पढने वालों के लिये प्रयोगशालायें बढाई गयी। पढाने के लिये प्राध्यापकों की संख्या बढते-बढते 150 तक हो गयी। लेकिन अब पिछले कई वर्षों से छात्रों की संख्या लगातार बढ रही है जबकि पढाने वाले प्राध्यापकों की संख्या लगातार घटती जा रही है।

राजनेताओं को क्या देर लगती है, फटाक से बयान जारी कर दिया कि सीटें बढा दी जायें। छात्रनेता खुश। उछलते-कूदते आ धमके प्रिंसिपल के पास, कहने लगे कि बढ़ी हुई सीटों पर दो दाखिला। उधर सरकार द्वारा अखबारी घोषणा से इतर सरकारी आदेश में लिख कर भेजा गया कि यदि कॉलेज के संसाधन इजाजत दें तो प्रिंसिपल सीटें बढा सकते हैं। अब कोई पूछने वाला हो इस सरकार से कि सीटों का निर्धारण ही संसाधनों के आधार पर किया जाता है। और राज्य का शायद ही कोई कॉलेज ऐसा हो जिसमें संसाधनों की क्षमता से अधिक छात्र न भर रखे हों।

लेकिन छात्र-नेताओं को लॉलीपॉप देकर सरकार तो हो गयी निश्चिंत, मुसीबत यहां कॉलेज में खड़ी हो गयी। बढ़ी सीटों पर दाखिले को लेकर छात्र हंगामे पर उतर आये। कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया। प्रिंसिपल महोदया ने जैसे-तैसे छात्रों को शान्त किया। पूरी स्थिति को गहराई से समझने के लिये इस संवाददाता ने कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीमति संतोष कुमारी से उनके कार्यालय जाकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि 1971 में यह कॉलेज मात्र 400 छात्रों के लिये बनाया गया था। धीरे-धीरे समय के साथ जब छात्रों की संख्या बढ़ने लगी तो इसकी क्षमता को 1500 तक बढ़ा दिया गया। जाहिर है क्षमता बढ़ाने के लिये नये कमरे बनाये गये, विज्ञान पढ़ने वालों के लिये प्रयोगशालायें बढ़ाई गयी। पढ़ाने के लिये प्राध्यापकों की संख्या बढ़ते-बढ़ते 150 तक हो गयी। लेकिन अब पिछले कई वर्षों से छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है जबकि पढ़ाने वाले प्राध्यापकों की संख्या लगातार घटती जा रही है। कोई पदोन्नति पर जा रहा है तो कोई सेवानिवृत हो रहा है, लेकिन इनकी जगह कोई भी नई नियुक्ति नहीं हो पा रही है। और तो और बच्चों के बैठने के लिये पर्याप्त कमरे तक नहीं हैं।

शेष पेज 2 पर

खबर दार

कार्पोरेट के लिये ओखा : आम आदमी के लिये चोखा

डॉलर के मुकाबले सस्ता रुपया जनता के हित में

सरकार, विपक्ष, कार्पोरेट, व्यावसायिक मीडिया रिजर्व बैंक, पूंजीवादी अर्थशास्त्री सब एक स्वर से डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत पर बढ़-चढ़ कर चिन्ता जता रहे है। रुपये के सस्ता होने से आम भारतीय का तो फ़ायदा ही होना है। उपरोक्त तमाम शासक तबकों को सस्ता डालर इस लिये चाहिये ताकि कार्पोरेट और दूसरे धनी प्रभावशाली तबकों की विदेशी जरूरतें सस्ते में पूरी हो सकें। दरअसल हुआ यह है कि पिछले 9-10 वर्ष में रुपये को अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में मंहगा होने दिया गया ताकि कार्पोरेट, राजनेता, नौकरशाह और व्यवसायी तबका सस्ते आयात का फ़ायदा उठा कर मोटा मुनाफ़ा कमा सके। साथ ही बड़े कार्पोरेट्स एवं बड़े राजनीतिज्ञों एवं नौकरशाहों ने विदेशों में कारखाने, कम्पनियां, रीयल एस्टेट हथियाने की जो मुहिम चला रखी थी उसे भी सुविधाजनक बनाया जा सके। इस दौर में रुपये के महंगा होने से मध्यम एवं छोटे दर्जे की तमाम देशी निर्यात इकाइयों को ठप होना ही था। इससे इन इकाइयों में व्यापक बेरोज़गारी तो आई ही, साथ ही विदेशी विशेषकर चीनी उपभोक्ता सामानों से भारतीय बाज़ार भी पट गये,जिन्होंने भारतीय बाज़ार को सामान पहुंचाने वाले उद्योग-धंधों को भी चौपट किया। अब जब रुपया सस्ता हो रहा है तो देश की उपरोक्त निर्यातक एवं उत्पादक इकाइयों को पुन:एक दराक में खोई उत्पादकता को प्राप्त करने में साल 2 साल तो लगेंगे ही।

- शेष पेज 2 पर